

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्व का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।



RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, बुधवार 12 मई 2021

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए

वर्ष-03, अंक- 221

महत्वपूर्ण एवं खास

पूर्व गृह मंत्री देशमुख पर दर्ज हुआ धन शोधन का मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। देशमुख के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धन शोधन रोकथाम कानून (पीएफएलए) की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय अब देशमुख और अन्य लोगों को पूछताछ के लिए तलब कर सकता है। बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर नियमित मामला दर्ज कर सीबीआई द्वारा की गयी आरंभिक जांच के बाद ईडी ने यह मामला दर्ज किया है। बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए घूस के आरोपों की जांच करने को कहा था।

पीएम मोदी और भूटान के पीएम त्शेरिंग के बीच हुई टेलीफोन वार्ता

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोते त्शेरिंग के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। भूटान के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी की वर्तमान लहर से लड़ने में भारत और भारतवासियों के साथ एकजुटता दिखाई। प्रधानमंत्री ने भूटान सरकार और भूटानवासियों को उनकी सद्भावनाओं और समर्थन के लिये धन्यवाद दिया। उन्होंने भूटान नरेश के नेतृत्व में महामारी के खिलाफ जग में भूटान की भूमिका की सराहना की और महामारी के खिलाफ किये जाने वाले प्रयासों के लिये लाइन-इन को शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त कि मौजूदा संकट से भारत और भूटान के बीच विशेष मैत्री को और बढ़ावा दिया जा सकता है। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बंध आपसी समझ, आपसी सम्मान, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोगों के बीच सौहार्द पर आधारित हैं।

पाबंदियों व लॉकडाउन से डेढ़ दर्जन राज्यों में घटे मामले

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश के 18 राज्यों में नाइट कर्फ्यू-लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की वजह से मामले घटने लगते नजर आ रहे हैं। हालांकि 16 राज्यों में कोरोना के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी भी हो रही है जो कि चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी और बताया कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात में प्रतिदिन कोरोना के नए मामलों में निरंतर कमी आ रही है। वहीं मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, जम्मू और कश्मीर, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में प्रतिदिन नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। मंत्रालय के अनुसार देश में 13 राज्यों में एक लाख से भी ज्यादा सक्रिय मामले हैं। जबकि 6 राज्यों में 50 हजार से एक लाख के बीच और 17 राज्यों में 50 हजार से कम सक्रिय मामले हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने किया सेंट्रल विस्टा परियोजना का बचाव

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण का बचाव किया। केंद्र ने कहा कि मजदूर इस काम में कोरोना कर्फ्यू से पहले ही जुट गए थे। निर्माण कार्य में लगे सभी मजदूरों का हेल्थ इश्योरेंस है और निर्माण साइट रहने समेत तमाम कोरोना बचाव संबंधी सुविधाएं भी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र ने कहा कि अदालत में याचिका झूठ के आधार पर दायर की गई है। अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी। बता दें कि इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी ही एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फिलहाल दखल देने से मना कर दिया था। बता दें कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन, एक नए आवासीय परिसर के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

देश में कोरोना संक्रमण से बढ़ रही मौतों का खौफ, पिछले 24 घंटे में आए 3.29 लाख से अधिक नए कोरोना मरीज

» राहत: एक दिन में 3.56 लाख से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना की मात, 3876 लोगों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच देश में बीते 24 घंटे में 3.29 लाख से अधिक नए कोरोना मरीज सामने आए और 3,876 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक दिन में 3.56 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने से एक राहत की आस भी सामने आई है।



केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले दो दिन से दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है।

लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,56,082 कोरोना मरीज कारण अपनी जान गंवाइ है। इस प्रकार देश में अब तक 2,49,992

1,90,27,304 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। इसके 62 दिन पहले 9 मार्च को 17,873 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई थी और 20,643 लोग ठीक हुए थे। फिलहाल देश में सक्रिय मामले बढ़कर 37,15,221 पहुंच गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या अमेरिका के बाद सबसे अधिक भारत में है।

दस राज्यों में 74 फीसदी नए मामले

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसा 74 फीसदी नए केस दस राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यूपी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। बता दें कि 7 मई को देश में सबसे ज्यादा 4,14,188 मामले दर्ज किए

गए थे। जबकि 8 मई को सबसे ज्यादा 4,187 मौतें हुई थीं। इसके बाद से संक्रमितों की संख्या और मौत का आंकड़ा कम हो रहा है। संक्रमण के नए मामलों में दिल्ली 10 राज्यों में आखिरी पायदान पर है।

महाराष्ट्र में हालातों में सुधार

महाराष्ट्र में 31 मार्च के बाद सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सबसे कम 37,236 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 51,38,973 हो गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इसी अवधि में 549 रोगियों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 76,398 तक पहुंच गई है। विभाग के मुताबिक, महाराष्ट्र में 31 मार्च को 39,544 नए मामले

सामने आए थे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सोमवार को 61,607 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई, जिसके बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 44,69,425 हो गई है। राज्य में फिलहाल 5,90,818 मरीज उपचाराधीन हैं।

17.27 करोड़ ने ली कोरोना वैक्सीन

देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक 17,27,10,066 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। बता दें कि 1 मई से कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। हालांकि, अभी यह सभी राज्यों में शुरू नहीं हुआ है।

कोरोना संकट में राज्यों के लिए दूत बना रेलवे

» अब तक 121 ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 4709 मीट्रिक टन जीवन रक्षक की हुई आपूर्ति

नई दिल्ली (आरएनएस)। रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब गति पकड़ती जा रही है। यह ट्रेन आठ राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति कर रही है। रेलवे ने अभी तक 121 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 295 टैंकरों में 4709 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सुनील शर्मा ने कहा है कि भारतीय रेल की प्रथमिकता इस समय देश में ऑक्सीजन आपूर्ति को जल्द से जल्द सुनिश्चित करना है। इसमें वह ऑक्सीजन आपूर्ति में आने वाली

परिवहन लागत को भी नहीं देख रही है। चाहे उसे दो टैंकर ले जाने हो या वह उन टैंकरों को लेकर ऑक्सीजन प्लांट तक जा रही है और वापस संबंधित राज्यों तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल से रेलवे ने अपनी ऑक्सीजन एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया था और अभी तक 121 फेरों के जरिए 295 टैंकरों में 4709 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। इनमें से 100 टैंकर दिल्ली को पहुंचाए गए हैं। उत्तर प्रदेश को 98, मध्य प्रदेश को 27, महाराष्ट्र को 18, हरियाणा को 40, तेलंगाना को 9 और राजस्थान को तीन टैंकर पहुंचाए गए हैं। इसके अलावा रेलवे की विभिन्न ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन इस समय 50 टैंकरों में 744 टन मेडिकल ऑक्सीजन लेकर रास्ते में हैं।

कोरोना के बाद महंगाई पर सियासत, केंद्र सरकार पर हमला कर घेरने में जुटी कांग्रेस

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के जारी रहने के बावजूद कांग्रेस के आचरण में कोई बदलाव नहीं आया है, जो केंद्र सरकार पर हमलों को तेज करके सियासत करने में जुटी हुई है। पिछले कई दिनों से वह कोरोना संक्रमण को दूसरी लहर में हो रही मौतों को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही थी। मंगलवार को वह महंगाई के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरते हुए दिखी।



महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा की लूट जारी है। पांच राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव खत्म होते ही भाजपा सरकार का तेल की लूट का खेल देबारा से शुरू हो गया है। मोदी सरकार ने पिछले आठ दिन में पेट्रोल 1.40 रुपए और डीजल को 1.63 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है।

सुरजेवाला ने ने आरोप लगाया कि सस्ता पेट्रोल-डीजल देने के वायदे पर सत्ता में आई मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने के लिए कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने की झूठी बहानेबाजी करती है। सच्चाई यह है कि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें काग्रेस के समय से एक चौथाई कम हैं। इसके बाद भी मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क को बार-बार बढ़ा कर जनता का तेल निकाल दिया है। सरकार जानबूझ कर लोगों को परेशान कर रही है। कांग्रेस का तर्क है कि 26 मई

2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, तब भारत की तेल कंपनियों को कच्चा तेल 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था, जो तत्कालीन डॉलर-रुपया के अंतरराष्ट्रीय भाव के अनुसार 6,330 रुपए प्रति बैरल बनता है, जिसका अर्थ है तेल लगभग 40 रुपए प्रति लीटर के भाव पर पड़ रहा था। उस समय पेट्रोल व डीजल क्रमशः 71.41 और 55.49 रुपए प्रति लीटर में उपलब्ध था, जो आज मोदी सरकार में क्रमशः 91.80 और 82.36 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है।

अब मिलेगा कोवैक्सिन, कोविशील्ड या स्पूतनिक का विकल्प

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब लोगों को मनचाही वैक्सीन लगाने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए कोविन पोर्टल पर बदलाव किए गए हैं। इसी कड़ी में अब कोविन पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने से पूर्व यह भी देखा जा सकेगा कि किस टीकाकरण केंद्र पर कौन सा टीका लग रहा है। वहीं उम्र के हिसाब से टीकाकरण केंद्रों खोजने की सुविधा भी प्रदान की गई है। क्योंकि सभी केंद्रों में सभी उम्र के लोगों को टीके नहीं लगते हैं।



कोविन पोर्टल पर बदलाव के अनुसार 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण से पूर्व पंजीकरण की सलाह दी जाती है। जबकि 18-44 आयु वर्ग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। कोविन पर पंजीकरण कराने के बाद टीकाकरण केंद्र के चयन की सुविधा दी गई है। इस दौरान पोर्टल पर यह भी प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस केंद्र पर कोविशील्ड लग रही है और कहां पर कोवैक्सीन। इससे लोगों को टीके का चयन करने की सुविधा मिलने लगी है। पहले सरकार ने कहा था कि लोगों को टीके के चयन की सुविधा नहीं दी जा सकती है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह बदलाव इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि जिन लोगों को दूसरी डोज लेनी है, उन्हें यह पता रहे कि किस केंद्र पर कौन सा टीका लग रहा है। दरअसल, कोवैक्सीन की आपूर्ति कम है तथा बहुत कम केंद्रों पर उसकी उपलब्धता है। दूसरे, एक-डेढ़ महीने पहले जिस केंद्र पर किसी व्यक्ति ने कोवैक्सीन लगाई है, वह जरूरी नहीं कि आगे भी उस केंद्र पर वही टीका उपलब्ध हो। फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी केंद्र पर टीका लगा सकता है। इसलिए कोविन पर यह जानकारी दी जा रही है कि किस केंद्र पर कौन सा टीका लगाया जा रहा है। टीके को क्लिक करके केंद्र सच करने की सुविधा भी है। इससे दूसरी खुराक लेने वालों को भी सहूलियत होगी।

टीकाकरण केंद्र सच करने की सुविधा भी- इसी प्रकार आयु के हिसाब से भी टीकाकरण केंद्र सच करने की सुविधा भी दी गई है। 45 से अधिक आयु के लोगों को जिन केंद्रों पर टीका लग रहा है, उनमें जरूरी नहीं कि 45 से कम वालों को भी लगता हो। इसलिए उम्र

के हिसाब से सच करने की सुविधा भी दी गई है। 45 से कम उम्र के लोगों के लिए ज्यादातर राज्यों ने अलग टीकाकरण केंद्र बनाये हैं। ऐसे में इन आयु वर्ग के लोगों को कोविन पर अपना टीकाकरण केंद्र सच करने में सहूलियत होती है। इसी प्रकार पिनकोड और जिले के आधार पर भी टीकाकरण केंद्र खोजने की सुविधा पोर्टल पर दी गई है।

बिना अवाइंटमेंट के टीकाकरण- पोर्टल पर यह भी सुविधा दी गई है कि 45 साल से अधिक उम्र के लोग बिना किसी केंद्र के चयन के भी पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण पूरा करने के बाद उनका चार अंकों का विशेष सुरक्षा कोड आ जाता है जिसे नोट कर या सेव कर वह किसी भी टीकाकरण केंद्र पर जा सकते हैं। और फोन नंबर और विशेष कोड बताकर वह टीका लगा सकते हैं।

टीके की दूसरी डोज लेने वालों को प्राथमिकता दे राज्य

» केंद्र सरकार ने वैक्सीन संकट के बीच राज्यों को दिया सुझाव

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्य सरकारों से अपील की है कि वे कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों को प्राथमिकता दें। कम-से-कम 70 फीसदी केंद्र से मिली वैक्सीन को उनके लिए रिजर्व रखें। साथ ही सरकार ने राज्यों से कहा है कि टीकों की हो रही बर्बादी को भी कम करें। मालूम हो कि देश में एक मई से टीकाकरण का तीसरा फेज चल रहा है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि सरकार ने राज्यों से

आग्रह किया गया है कि जिन लोगों ने पहली डोज लगावा ली है, उन्हें दूसरी डोज लगाने के लिए प्राथमिकता दें। इस संबंध में राज्य सरकारों से मिली कुल वैक्सीन स्पलाई में से 70 फीसदी डोज को दूसरी डोज के लिए रिजर्व रखें और बाकी बची 30 फीसदी डोज को लोगों के लिए पहली डोज के तौर पर दी जाए। बयान में आगे कहा गया है, हालांकि यह सांकेतिक है। राज्यों को इसे बढ़ाकर 100 फीसदी तक ले जाने की छूट है। कोविन पर राज्यवार संख्या उनके उद्देश्यों के लिए राज्यों के साथ साझा की गई है। केंद्र ने यह भी बताया है कि राज्य सरकारों से दोनों डोज लेने के महत्व को दिखाने के लिए कैपेन चलाने के लिए कहा गया है।

केंद्र ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ कोविड टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और कोविड-19 से निपटने के लिए बनायी गयी प्रौद्योगिकी एवं डेटा प्रबंधन सशक्त समूह के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कोविड-19 टीका प्रशासन विशेषज्ञ समूह के सदस्य डॉ. आर एस शर्मा ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की। वैश्विक स्तर पर इस तरह के सबसे बड़े अभ्यासों में से एक, देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। बाद में इसका व्यापक रूप से विस्तार किया गया और राष्ट्रीय



कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए उदार मूल्य निर्धारण एवं त्वरित मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की। वैश्विक स्तर पर इस तरह के सबसे बड़े अभ्यासों में से एक, देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। बाद में इसका व्यापक रूप से विस्तार किया गया और राष्ट्रीय

सचिव ने राज्य सुनिश्चित करेंगे कि पहली खुराक लेने वाले सभी लाभार्थियों को दूसरी खुराक के लिए प्राथमिकता दी जाए। दूसरी खुराक का इंतजार कर रहे बहुत सारे लाभार्थियों की जरूरत पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया।

इस संबंध में, राज्य भारत सरकार के माध्यम से मिले टीकों में से कम से कम 70 प्रतिशत टीके दूसरी खुराक के लिए और बाकी 30 प्रतिशत पहली खुराक के लिए रख सकते हैं। यह हालांकि सांकेतिक है। राज्यों को इसे 100 प्रतिशत तक बढ़ाने की स्वतंत्रता है। कोविन पर राज्यवार पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली एक विस्तृत प्रस्तुति के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य

राज्यों से टीके की दो खुराक के साथ पूर्ण टीकाकरण के महत्व को रेखांकित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उन राज्यों का विवरण प्रस्तुत किया जिन्होंने प्राथमिकता समूहों (जैसे कि 45+, एफएलडब्ल्यू और एचसीडब्ल्यू) एवं अन्य के उच्च कवरेज को सुनिश्चित किया है, और राज्यों से आग्रह किया कि वे सुनिश्चित करें कि प्राथमिकता वाले समूहों को टीका लगाया जाए। भारत सरकार के माध्यम से प्रदान किए जा रहे कोविडटीकों के बारे में राज्यों को पहले से पारदर्शी तरीके से सूचित किया गया है। बेहतर और ज्यादा कारगर योजना निर्माण में राज्यों की मदद करने के लिए उन्हें अग्रिम

रूप से आगामी पखवाड़े के लिए टीके के आवंटन के बारे में बता दिया गया है। 15-31 मई की अवधि के लिए अगला आवंटन उन्हें 14 मई को दिया जाएगा। यह बताया गया कि राज्य अपने टीकाकरण सत्रों की योजना बनाने के उद्देश्य से अगले 15 दिनों के लिए खुराक के आवंटन के बारे में जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। राज्यों से टीका अपव्यय को कम करने का भी आग्रह किया गया। हालांकि समग्र स्तरों में काफी कमी आई है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कई राज्य हैं जिन्हें अभी भी अपव्यय को कम करने की जरूरत है। टीकों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीकों को

लेकर पुन-प्रशिक्षण और पुन-व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया था। राष्ट्रीय औसत से अधिक सभी अपव्यय को उसके बाद उस राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के बाद के आवंटन से समायोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में, यह भी बताया गया कि कुछ राज्य एक नकारात्मक अपव्यय की जानकारी देने में सक्षम हैं, क्योंकि अच्छी तरह से प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रति शीपी से अधिकतम खुराक निकाल सकते हैं, जो आम तौर पर वैसे चिह्नित है। राज्यों को 'भारत सरकार के अलावा' दूसरे माध्यम से खरीद के बारे में भी बताया गया था जो कि टीकाकरण के तीसरे चरण की त्वरित रणनीति के तहत खोला गया है।